भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 745

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

100 दिवसीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान का प्रभाव

745. डॉ. भोला सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 100 दिवसीय क्षय रोग उन्मूलन अभियान में संक्रमण दर को कम करने, उपचार में देरी से बचने और उपचार को बीच में छोड़ने की दर में कमी लाने पर क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शीघ्र पहचान, उपचार की बेहतर सुविधा और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है; और
(घ) क्या सरकार मलेरिया और डेंगू जैसी अन्य संक्रामक बीमारियों के लिए भी इसी तरह के गहन अभियान चलाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) सरकार ने टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को गति देने के लिए 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है। यह अभियान टीबी के छूटे हुए मामलों को खोजने, टीबी से होने वाली मौतों को कम करने और नए मामलों को रोकने के लिए नए दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। जन भागीदारी के हिस्से के रूप में, निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय के स्वयंसेवक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता कमजोर आबादी को संगठित करने, टीबी के संकेतों/लक्षणों के बारे में समुदाय में जागरूकता बढ़ाने, इसके कलंक को कम करने और कमजोर आबादी के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए अभियान का समर्थन करते हैं।

347 जिलों में 100 दिनों के सघन टीबी उन्मूलन अभियान की शुरूआत से लेकर अब तक 4.94 लाख नि-क्षय शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, 5.63 करोड़ संवेदनशील व्यक्तियों की जांच की गई है और 1.59 लाख नए टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, 86,748 नए नि-क्षय मित्र पंजीकृत किए गए हैं और टीबी रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को 1.12 लाख खाद्य टोकरियाँ वितरित की गई हैं।

सरकार द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शीघ्र पहचान, बेहतर उपचार पहुंच और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजनाओं के माध्यम से उच्च टीबी बोझ वाले क्षेत्रों में लक्षित अंतक्षेप।
- टीबी रोगियों को नि:शुल्क दवाओं और निदान का प्रावधान।
- प्रमुख कमजोर और सह-रुग्ण आबादी में अभियानों के माध्यम से सक्रिय टीबी मामले की खोज।
- टीबी स्क्रीनिंग और उपचार सेवाओं के साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एकीकरण।
- टीबी मामलों की सूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- उप-जिला स्तर तक आणविक निदान प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- दवा प्रतिरोधी टीबी के लिए सभी मौखिक, छोटे, सुरक्षित और अधिक प्रभावी उपचार की शुरूआत।
- पोषण सहायता के लिए निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति रोगी 1000 रुपये प्रति माह प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
- निक्षय मित्र पहल के अंतर्गत टीबी रोगियों और उनके घरेलू संपर्कों को अतिरिक्त पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक सहायता का प्रावधान।
- टीबी रोगियों और कमजोर आबादी के संपर्कों के लिए टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- निक्षय पोर्टल के माध्यम से सूचित टीबी मामलों की ट्रैकिंग।
- इस कलंक को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार अंतक्षेप।

मंत्रालय मौसमी आवश्यकताओं के आधार पर चिन्हित भौगोलिक क्षेत्रों और जनसंख्या में मलेरिया और डेंगू जैसी अन्य संक्रामक बीमारियों के लिए समय-समय पर गहन अभियान चलाता है।

****